दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, शनिवार 22 दिसम्बर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-83

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रंप के फैसले से नाराज रक्षा मंत्री मैटिस ने दिया इस्तीफा

संयुक्त राष्ट्र (आरएनएस)। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने रक्षा मंत्री के इस्तीफे की एक कॉपी को रिलीज किया है। मैटिस का यह इस्तीफा ट्रंप की ओर से सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के संकेत के बाद आया है। प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया है।

सोमालिया में अमेरिकी सेना के हवाई हमले में 11 आतंकवादी ढेर

मोगादिशु (आरएनएस)। सोमालिया की राजधानी के बाहरी क्षेत्र में अमेरिकी सेना के हवाई हमलों में आतंकवादी संगठन अल-शबाब के 11 आतंकवादी मारे गए हैं।

ग्राहकों को धोखा देने पर 10 लाख का जुर्माना

मिलावट करने पर होगी उम्रकैद

नईदिल्ली (आरएनएस)। गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सरकार सख्त कदम उठाया है. गुरुवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को लोकसभा में हंगामे के बीच सरकार ने पारित कर दिया है. इस बिल के तहत अगर कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो उसे दो साल की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. अपराध दोहराए जाने पर जुर्माने की राशि 50 लाख रुपये तक और कैद की अवधि पांच साल तक हो जाएगी. साथ ही, मिलावट करते हुए पाए जाने पर उम्रकैद हो सकती है. इसके अलावा एक एजेंसी बनाई जाएगी जो ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेगी और कंपनियों पर कार्रवाई करेगी.

लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी जुबैर भट्ट गिरफ्तार

पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर और गंडेरबल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जुबैर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी जुबैर भट लश्कर का एक एक्टिव आतंकी बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो वह नए साल पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश बना रहा था।

राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, पारा 4 डिग्री पहुंचा

नईदिल्ली (आरएनएस)। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य ठंड की गिरफ्त में आ गए हैं. राजधानी में शुक्रवार सुबह घने कोहरे और सर्द हवाओं ने कड़ाके की ठंड का एहसास कराया. मौसम विभाग ने अभी ठंड और बढ़ने की आशंका जताई है. गुरुवार को पारा गिरकर चार डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था. शहर का तापमान इस मौसम के सबसे निचले स्तर पर था.

केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, भूस्खलन से 9 मजदूरों की मौत

राम्बरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, भूस्खलन की वजह से 9 मजदूरों की मौत हो गई है और कई मजदूरों के दबे होने के आशंका जताई जा रही है।

एमपी में 60 साल से ज़्यादा उम्र के किसानों को मिलेगी एक हजार रुपए महीने पेंशन

सिर्फ खेती पर आश्रित कम जमीन वालों को ही होगा फ़ायदा- सूत्र

भोपाल। एमपी में 60 साल से ज़्यादा उम्र के किसानों को मिलेगी एक हज़ार रुपए महीने पेंशन, आयकर रिटर्न भरने वाले या किसी दूसरी नौकरी या व्यवसाय पर आश्रित किसानों को नही मिलेगा योजना का फ़ायदा, सिर्फ खेती पर आश्रित कम जमीन वालों को ही होगी फ़ायदा- सूत्र

पीसीए से बाहर हो सकते हैं 4-5 बैंक

सरकार 83 हजार करोड़ डालेगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों में एनपीए की स्थिति का जायजा पूरा हो चुका है और सरकारी बैंकों में 83,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह पूंजी न सिर्फ आरबीआई की पाबंदी (पीसीए) झेल रहे बैंकों में ही डाली जाएगी, बल्कि कुछ ऐसे सरकारी बैंकों में भी डाली जाएगी, जिनपर आने वाले समय में आरबीआई बड़े लोन देने पर पाबंदी लगा सकता है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2018-2019 में सरकारी बैंकों में 42 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को अनुपूरक अनुदान की मांग की दूसरी किस्त के तहत सरकारी बैंकों में 41 हजार करोड़ रुपये की रकम डालने के लिए संसद की मंजूरी मांगी। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में बैंकों में कुल रिकैपिटलाइजेशन 65 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, यह पूंजी बेहतर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों को दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि बैंकों की कर्ज देने की क्षमता में हुआ सुधार हुआ है और सरकारी बैंकों ने हर पैमाने पर बेहतर प्रदर्शन किया है। पहली छमाही में बैंकों ने 60,726 करोड़ की रिकवरी की।

केंद्रीय वित्तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार ने कहा, तीन बैंक पीसीए के थ्रेसहोल्ड 1 के दायरे में हैं और 4-5 बैंकों को इस साल अतिरिक्त पूंजी दी जाएगी। 4-5 बैंकों के पीसीए के दायरे से बाहर निकलने की उम्मीद है।

क्या है पीसीए

पीसीए की व्यवस्था के तहत बैंकों से कुछ रिस्की गतिविधियों से परहेज करने, कामकाजी दक्षता बढ़ाने और पूंजी की हिफाजत पर जोर देने के लिए कहा जाता है। हालांकि कई बैंकों को डर है कि पीसीए प्रोग्राम लंबे समय तक चलने से बड़े और कर्ज पाने की पात्रता रखने वाले क्लाइंट्स छिटक सकते हैं और ये बैंक कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं।

नकदी फंसी

सरकार का मानना है कि पीसीए के तहत इन बैंकों को डालने से लेनदेन लायक काफी नकदी फंस गई है। ये बैंक मुख्य तौर पर रिटेल, मॉर्गेज और छोटे लोन तक सीमित रह गए हैं और क्रेडिट क्रिएशन में भागीदार नहीं बन पा रहे हैं। पीसीए में आए ये 11 बैंक भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री का करीब एक चौथाई हिस्सा हैं और इनका आकार देश के समूचे नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सेक्टर (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर) के लगभग बराबर है।

अब देश में चल रहे हर कंप्यूटर पर होगी सरकार की नजर

10 एजेंसियों को मिला जासूसी का अधिकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय केन्द्र सरकार ने देश में किसी भी कंप्यूटर में डाटा जांच हेतु

गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा एवं सूचना विभाग ने इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 69 (1) के तहत एजेंसियों को यह अधिकारी दिया है। यही नहीं मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में उन 10 एजेंसियों की सूची भी जारी की गई है, जो 10 केंद्रीय एजेंसियो को अधिकृत कर दिया है। अब देश के हर कम्प्यूटर पर सरकार की नजर रहेगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 10 केन्द्रीय एजेंसियों को नियुक्त कर किसी भी कंप्यूटर में सेंधमारी कर जासूसी करने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार देश की ये सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जेनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकता है। आपके कंप्यूटर की कभी भी जांच कर सकेंगी। मंत्रालय के आदेश के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट (रॉ), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की जासूसी की मंजूरी दी गई है।

शारजाह में छत से लटका मिला भारतीय नागरिक

दुबई (आरएनएस)। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर में भारतीय व्यक्ति अपने कमरे की छत से लटका पाया गया। मीडिया में

आई खबरों में बुधवार को यह जानकारी दी गई। मंगलवार की शाम में हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को फोन से मिली।

इसके बाद पुलिस शारजाह के अल रोला क्षेत्र स्थित घर में पहुंची जहां संबंधित व्यक्ति फांसी से लटका हुआ मिला। रिपोर्ट के अनुसार मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका।

पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

एक ही राज्य के 700 पादरियों पर यौन शोषण का आरोप

शिकागो (आरएनएस)। अमेरिका के इलिनोइस राज्य में करीब 700 पादरियों पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप है, जो इससे पहले

कैथॉलिक चर्च की ओर से बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा है। अमेरिका के मध्य पश्चिमी राज्य के शीर्ष अभियोजक ने यह खुलासा किया है। इलिनोइस की अटॉर्नी जनरल लीसा मैडिगन ने बुधवार को कहा कि चर्च ने ऐसे पादरियों की संख्या 185 बताई थी, लेकिन उनके कार्यालय की जांच में यह संख्या काफी कम पाई गई है। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की ओर से जारी बयान में शोषण के आरोपों से निपटने में चर्च की असमर्थता की आलोचना की गई है। कार्यालय का कहना है कि आरोपों की जांच अधूरी रही और कई मामलों में कानून का पालन नहीं किया गया।

सरेंडर का समय बढ़ाने सज्जन कुमार की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

नईदिल्ली (आरएनएस)। हाईकोर्ट ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले के दोषी करार दिए गए सज्जन कुमार की सरेंडर करने की समय अवधि बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने सरेंडर के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से 30 दिन का समय मांगा था. हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसा ठोस कोई कारण नहीं है कि सरेंडर करने की समयसीमा बढ़ाई जाए.

उन्हें इसी हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी. कोर्ट ने

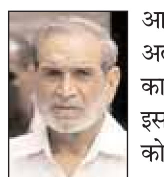

उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था. उम्रकैद के अलावा उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे.

ये मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर 1984 का है. दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. मामले में बाक़ी लोगों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है.

करीब 34 साल बाद 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने सोमवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उनको दंगे के लिए दोषी माना और उम्रकैद की सजा दे दी. उनको आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है. इस मामले में उन्हें पहले निचली अदालत ने बरी कर दिया था.

जस्टिस एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने 29 अक्टूबर को सीबीआई, दंगा पीड़ितों और दोषियों की ओर से दायर अपीलों पर दलीलें सुनने का काम पूरा करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. मामले की शुरुआत 1984 से होती है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे. दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही. हिंसा की इसी आग में राजधानी के दूसरे पंजाबी बहुल इलाकों के साथ पूर्वी त्रिलोकपुरी इलाके में करीब 95 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग सौ घरों को जला दिया गया था.

क्रिसमस पर संसद में तीन दिन का अवकाश

नई दिल्ली (आरएनएस)। क्रिसमस के मौके पर संसद के दोनों सदनों में तीन दिन का अवकाश रहेगा। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को पहले से ही अवकाश घोषित था।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज सभा की सहमति से 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को भी अवकाश की घोषणा की। इससे पहले राज्यसभा में 19 दिसंबर को ही सभापति एम. वेंकैया नायडू ने 24 और 26 दिसंबर को अवकाश होने की घोषणा कर दी थी।

एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो जरूरी कागजात सभा पटल पर रखे जाने के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कई सदस्यों ने यह माँग की है कि 24 और 26 दिसंबर को सदन की बैठक न हो।

इस पर अध्यक्ष ने सभा से उसकी सहमति माँगी और सदस्यों के सहमत होने पर 24 और 26 दिसंबर को सदन में अवकाश की घोषणा कर दी। इस प्रकार अब सदन की अगली बैठक गुरुवार 27 दिसंबर को होगी।

ईवीएम में छेड़छाड़ मुमकिन नहीं: सीईसी

नई दिल्ली (आरएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाये जाने पर दुख व्यक्त करते हुये कहा है कि मतदान की यह सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति है क्योंकि मशीन गलत रखरखाव की शिकार तो हो सकती है, लेकिन इसमें छेड़छाड़ मुमकिन ही नहीं है। नवनियुक्त सीईसी अरोड़ा ने ईवीएम पर राजनीतिक दलों के आरोपों के दायरे में अब चुनाव आयोग के भी आने के मुद्दे पर कहा कि चुनाव में मतदाताओं के बाद

राजनीतिक दल ही मुख्य पक्षकार होते हैं। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस बात से मुझे क्षोभ होता है, हमने ईवीएम को 'फुटबॉल' बना दिया। किसी दल विशेष के पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं आने पर फ इसका ठीकरा ईवीएम पर फ ड़ने की प्रवृत्ति के बारे में अरोड़ा ने दलील दी कि 2014 के लोकसभा चुनाव का परिणाम, इसके बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा और अब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव तथा तमाम उपचुनाव के परिणाम बिल्कुल भिन्न रहे। अरोड़ा ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव परिणाम की व्याख्या अपनी सुविधानुसार करने का जिक्र करते हुये कहा कि ईवीएम महज एक मशीन है जो आंकड़े दर्ज कर उनकी गिनती करती है। मशीन में खास प्रोग्रामिंग कर विशेष परिणाम हासिल करने की संभावना को वह पूरी तरह से नकार सकते हैं।

पांच राज्यों के चुनाव में ईवीएम की मतदान केन्द्रों से इतर अन्य स्थानों पर बरामदगी के सवाल पर अरोड़ा ने कहा कि मशीन में छेड़छाड़ करना और इसका गलत रखरखाव दो अलग मुद्दे हैं। जो शिकायतें इन चुनावों के दौरान मिलीं, वे कर्मचारियों द्वारा गलत रखरखाव की श्रेणी में आती हैं। इस तरह के जो चार-पांच मामले सामने आये हैं, हालांकि यह संख्या नगण्य है लेकिन फिर भी आयोग की कोशिश इस संख्या को शून्य पर लाने की है।

सीबीआई कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी किया

मुंबई (आरएनएस)। सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 13 साल बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट का कहना है कि सबूतों की कमी की वजह से आरोपियों को मामले से रिहा किया जाता है। कोर्ट ने गवाहों के बयान से पलटने पर यह भी कहा कि अगर कोई बयान न दे तो इसमें पुलिस की गलती नहीं है।

सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में स्पेशल सीबीआई जज ने अपने आदेश में कहा कि सभी गवाह और सबूत साजिश और हत्या को साबित करने के लिए काफी नहीं थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े परिस्थितिजन्य सबूत भी पर्याप्त नहीं है। सीबीआई कोर्ट के अनुसार, तुलसीराम प्रजापति को एक साजिश के तहत मारा गया, यह आरोप भी सही नहीं है।

सीबीआई कोर्ट के जज ने कहा, सरकारी मशीनरी और अभियोजन पक्ष ने काफी प्रयास किया और 210 गवाहों को सामने लाया गया लेकिन उनसे कोई संतोषजनक सबूत नहीं मिल पाया और कई गवाह अपने बयान से पलट गए। इसमें अभियोजक की कोई गलती नहीं है अगर गवाह नहीं बोलते हैं।

राजधानी में हुआ महागठबंधन का ऐलान

उपेंद्र कुशवाहा भी हुए शामिल

नई दिल्ली (आरएनएस)। मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने और एनडीए से नाता तोड़ने के बाद राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को यूपीए का हिस्सा बन गए। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने यूपीए का दामन थामा। उन्होंने कहा कि एनडीए में उनका अपमान हो रहा था। कुशवाहा के यूपीए में शामिल होने का ऐलान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बिहार में महागठबंधन के नेताओं की

मौजूदगी में किया। इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कुशवाहा का महागठबंधन में स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला।

देश में अघोषित आपातकाल: तेजस्वी

उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन में आने पर स्वागत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि यह संविधान और देश बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में अघोषित इमर्जेंसी है और पीएम मोदी घटक दलों पर भी तानाशाही कर रहे हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि यह उनके खिलाफ लड़ाई है, जिन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया, गुमराह करने का काम किया।

बीजेपी की गणतंत्र बचाओ रथयात्रा को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

कोलकाता (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। गणतंत्र बचाओ यात्रा को मंजूरी मिलने से राज्य की ममता सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्य सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का हवाला

ममता सरकार को झटका

देकर रथयात्रा को मंजूरी देने से इनकार किया था। रथयात्रा रोके जाने पर ममता सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जमकर निशाना साधा था और खुद मोर्चे पर जुट गए थे। कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा से होने वाला खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता।

साथ ही यह निर्देश दिया कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कहीं भी कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो।